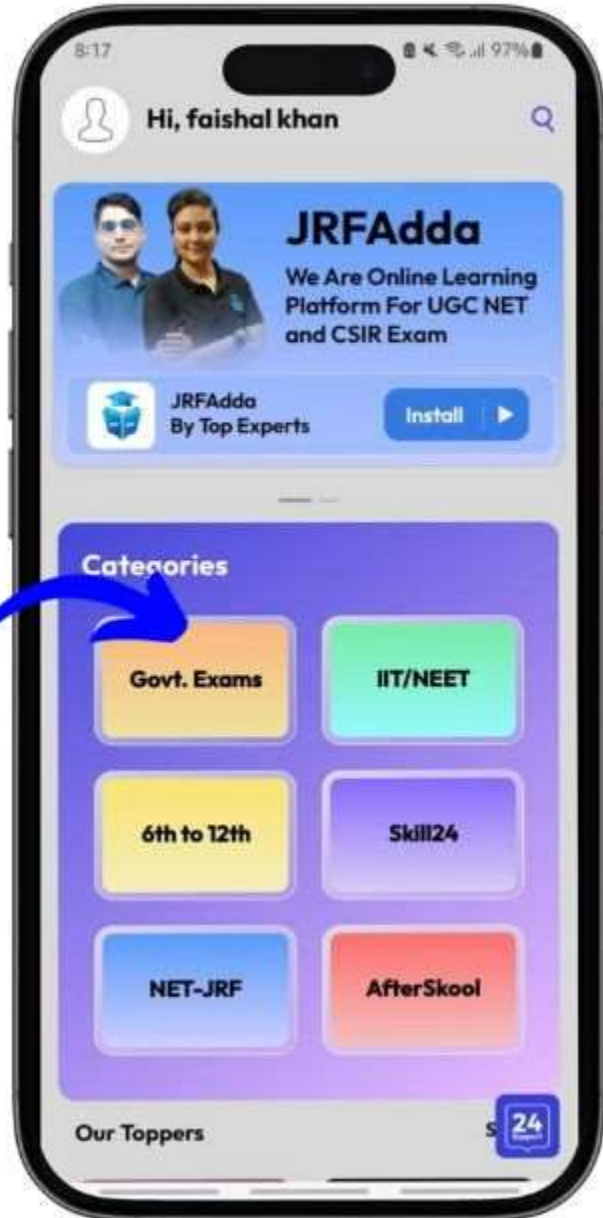


# Complete Gk/Gs Notes

**BY BHUNESH SIR**



# Step-1



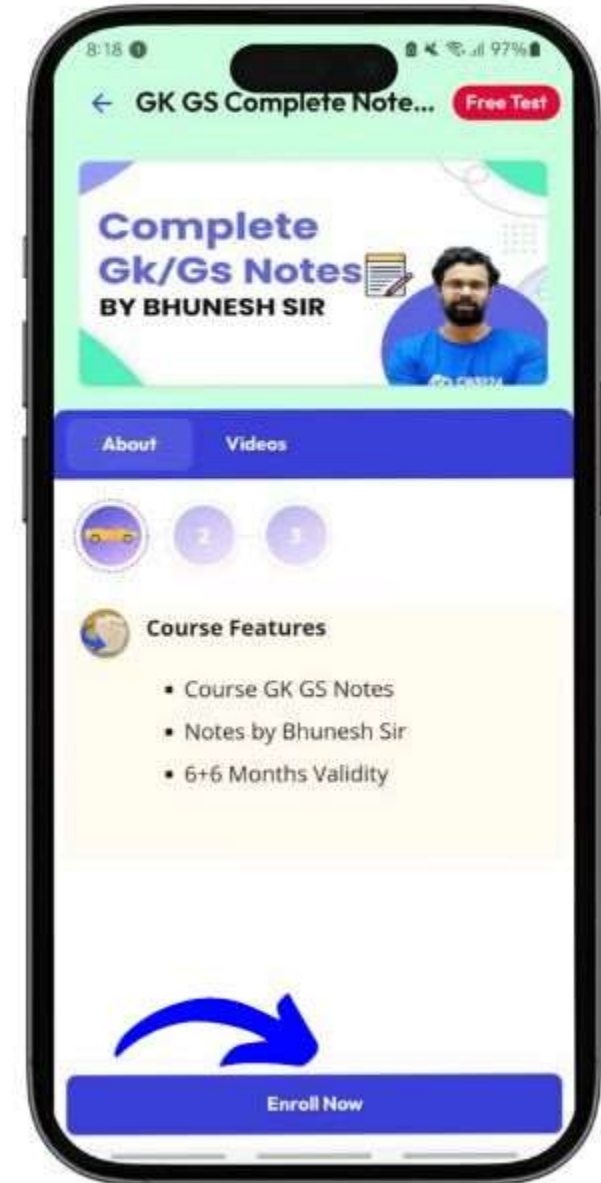
# Step-2



# Step-3



# Step-4



# INDIAN POLITY

## THE CONSTITUTION OF INDIA THROUGH IMPORTANT ARTICLES

महत्त्वपूर्ण अनुच्छेदों के माध्यम से भारतीय संविधान का अध्ययन

BY BHUNESH SIR

PART -3

CGL- 21th July 2023

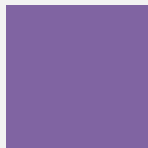
# Daily 3 most Important classes



**5 am -> 10 min current affairs show**



**7 am -> The Hindu Analysis**



**8 am -> Daily SSC CGL/ CHSL Specific GK class**



# Class24

## App download



**Class pdf**



**10 Questions test related to  
this class**





भारतीय संविधान में मूल  
अधिकार

**FUNDAMENTAL  
RIGHTS IN INDIAN  
CONSTITUTION**





## Table of content/ सामग्री की तालिका

- 1) Why Fundamental rights are needed
- 2) Articles 12 to 35 in Short
- 3) Articles 12 to 35 in Details
- 4) Suspension of the FR
- 5) Amendments of the FR
- 6) Facts
- 7) Previous year questions asked from FR in CGL/ CHSL.



## Importance' of Fundamental Rights/ मौलिक अधिकारों का महत्व

(i) Fundamental Rights create a feeling of security amongst the minorities in the country.

(ii) No democracy can function in the absence of basic rights such as freedom of speech and expression.

(iii) Fundamental Rights grant the standards of conduct, citizenship, justice and fair play.

j) मौलिक अधिकार देश में अल्पसंख्यकों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं।

(ii) कोई भी लोकतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे बुनियादी अधिकारों के अभाव में कार्य नहीं कर सकता है।

(iii) मौलिक अधिकार आचरण, नागरिकता, न्याय और निष्पक्ष खेल के मानक प्रदान करते हैं।

## Importance' of Fundamental Rights/ मौलिक अधिकारों का महत्व

- iv) They act as a check on the government.
- v) Fundamental Rights allow human beings to live a dignified life.
- vi) Fundamental Rights are extremely important for growth, development and prosperity of a nation and its citizens.

- iv) वे सरकार पर अंकुश के रूप में कार्य करते हैं।
- v) मौलिक अधिकार मनुष्य को सम्मानजनक जीवन जीने की अनुमति देते हैं।
- vi) किसी राष्ट्र और उसके नागरिकों की वृद्धि, विकास और समृद्धि के लिए मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

# भारतीय संविधान में मूल अधिकार

## FUNDAMENTAL RIGHTS IN INDIAN CONSTITUTION

- संविधान के भाग तीन (अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35) में मूल अधिकारों संबंधी प्रावधान है। इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
- इनमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात (अनु. 352) की स्थिति में अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति नहीं है।
- Part three of the Constitution (Article 12 to Article 35) contains provisions on Fundamental Rights. These are derived from the Constitution of the United States.
- These can be amended and in the event of a national emergency (Article 352) under Article 359 the President does not have the power to suspend the enforcement of Fundamental Rights guaranteed in Articles 20 and 21 of the Constitution.

CGL - 20<sup>th</sup> July 2023

# भारतीय संविधान में मूल अधिकार

## FUNDAMENTAL RIGHTS IN INDIAN CONSTITUTION

CGL 5.08.2017

CGL 22, 6.12.2022

- मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन (1979 ई.) के द्वारा संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31 व अनुच्छेद 19(1)(च)) को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 (ए) के अन्तर्गत क़ानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है।

- The original constitution had seven fundamental rights, but by the 44th Constitutional Amendment (1979 AD), the right to property (Article 31 and Article 19 (1) (f)) was removed from the list of Fundamental Rights and it was replaced by Article 300 (A) of the Constitution and since then it has been kept as a legal right.

CGL - Pre 12.12.2022, 13.12.2022, 23.02.2014, 21.04.2013, 2.08.2019,

5.12.2022

CHSL- 16.11.2014, 17.03.2019

# भारतीय संविधान में मूल अधिकार

## FUNDAMENTAL RIGHTS IN INDIAN CONSTITUTION

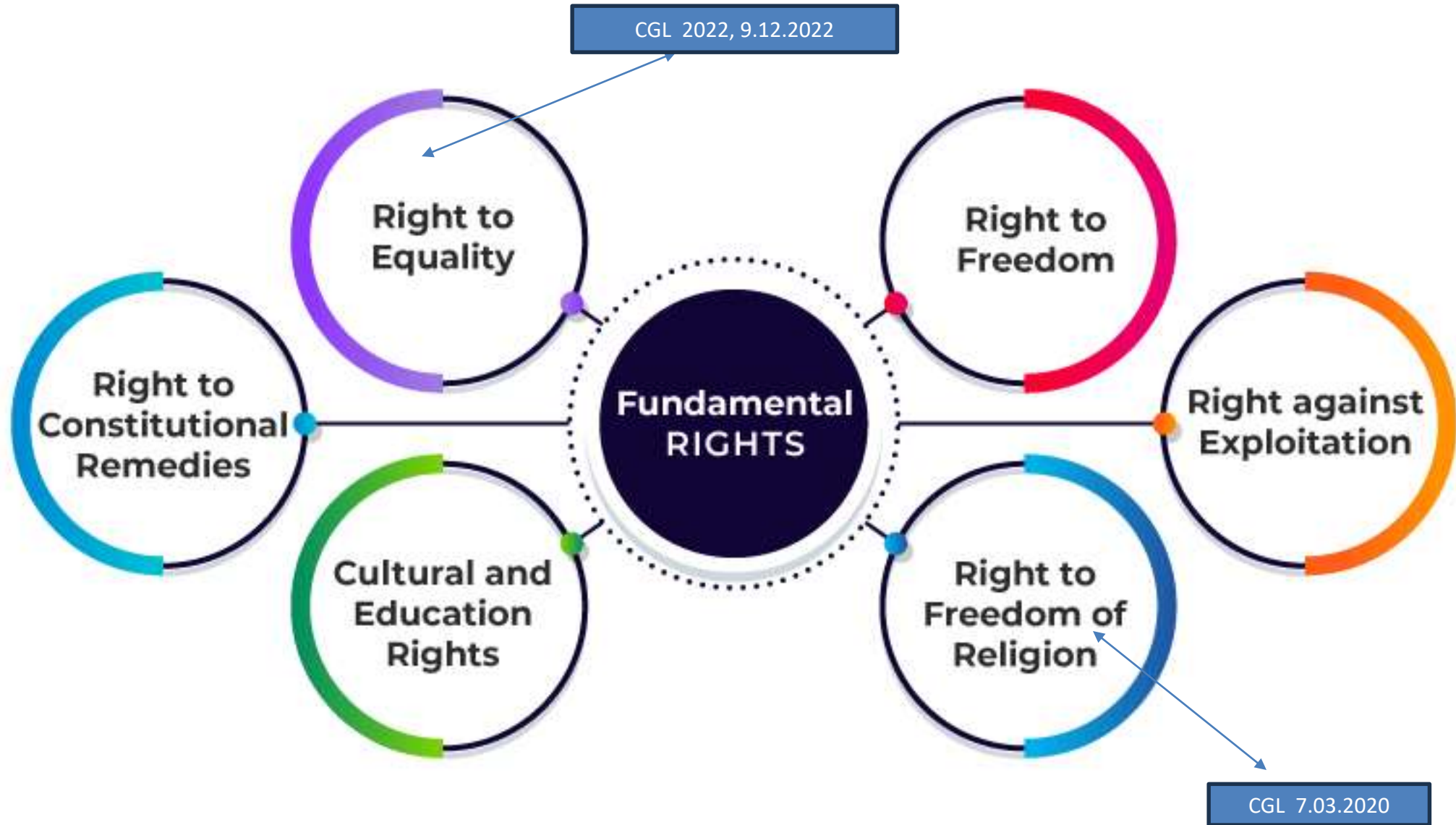
CGL - 26<sup>th</sup> July 23

भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त हैं:

- 1. समता या समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18)
- 2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)
- 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24)
- 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)
- 5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)
- 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

- Indian citizens have the following fundamental rights:
- 1. Right to Equality (Article 14 to Article 18)
- 2. Right to freedom (Articles 19 to 22)
- 3. Rights against exploitation (Articles 23 to 24)
- 4. Right to religious freedom (Articles 25 to 28)
- 5. Cultural and Educational Rights (Articles 29 to 30)
- 6. Constitutional Remedy (Article 32)





## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### साधारण / General

अनुच्छेद	विवरण
12	परिभाषा / Definition
13	मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights

## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### Article - 13

- अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत विधियां शून्य हो जाएंगी। दूसरे शब्दों में, यह न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है।
- इस शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) को प्रदान किया गया है जो कि किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर विधि को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकता है।
- Article 13 declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void. In other words, it provides for the doctrine of judicial review.
- This power has been conferred on the Supreme Court (Article 32) and the high courts (Article 226) that can declare a law unconstitutional and invalid on the ground of contravention of any of the Fundamental Rights.

## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### समता का अधिकार / Right to Equality

अनुच्छेद	विवरण
14	विधि के समक्ष समानता / Equality before law
15	धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध / Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth
16	लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता / Equality of opportunity in matters of public employment
17	अस्पृश्यता का अंत / Abolition of Untouchability
18	उपाधियों का अंत / Abolition of Titles

## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### 1. समता या समानता का अधिकार:

- **अनुच्छेद 14:** विधि के समक्ष समता- इसका अर्थ यह है कि राज्य सही व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा।
- **अनुच्छेद 15:** धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेद-भाव का निषेध- राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म-स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा।

### 1. Right to Equality:

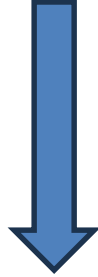
- **Article 14: Equality before law**- This means that the state will make uniform laws for the right people and apply them in a uniform manner.
- **Article 15: Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth** - citizens will not be discriminated depending on religion, race, caste, sex and place of birth etc. by the state in any area of life.

CHSL- 22.03.2018, 21.10.2020,  
09.08.21,  
CGL- 4.03.202, 2022, 12.12.2022,

CGL Mains 2022,  
03.03.2023



**Article 14** equality before law, the phrase equality before the law has been borrowed from Britain.



CGL 20.7.2014, 2.09.2016,  
CHSL - 22.03.2018

**अनुच्छेद 14** कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता का वाक्यांश ब्रिटेन से लिया गया है।

## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### समता या समानता का अधिकार:

- **अनुच्छेद 16:** लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता- राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद\* - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग।
- \*103वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 16(6) जोड़ा गया है और सामान्य श्रेणी से 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' (ईडब्लूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।

### Right to Equality:

- **Article 16:** Equality of opportunity in the matter of public employment- There will be equality of opportunity for all citizens in subjects related to planning or appointment to a post under the state. Exception \* - Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes.
- Article 16 (6) has been added to it by the \*103rd Constitutional Amendment and 10 per cent reservation has been provided to the 'Economically Weaker Section' (EWS) of the general category.

## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

CGL – 4.03.2020

### समता या समानता का अधिकार:

- **अनुच्छेद 17:** अस्पृश्यता का अंत- अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
- **अनुच्छेद 18:** उपाधियों का अंत- सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाए अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है।

### Right to Equality:

- **Article 17:** Abolishment of Untouchability - it has been declared a punishable offence for the abolition of untouchability.
- **Article 18:** Abolishment of Titles - no other title will be conferred by the state except for honours related to army or education. No citizen of India can accept any title from any other country without the permission of the President.

CGL – 16.08.2017

## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### स्वतंत्रता का अधिकार / Right to Freedom

अनुच्छेद	विवरण
19	वाक-स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण / Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.
20	अपराधों के लिए दोष-सिद्धि के संबंध में संरक्षण / Protection in respect of conviction for offences
21	प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण / Protection of life and personal liberty
22	कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण / Protection against arrest and detention in certain cases

## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### स्वतंत्रता का अधिकार / RIGHT TO FREEDOM (Art. 19-22)

**अनुच्छेद 19-** मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 हैं:

- 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- 19(1)(b) शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता
- 19(1)(c) संघ बनाने की स्वतंत्रता

**Article 19(1)** provides that all citizens shall have the right- (originally 7, now 6)

- 19(1)(a) - to freedom of speech and expression;
- 19(1)(b) - to assemble peaceably and without arms;
- 19(1)(c) - to form associations or unions;



## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### स्वतंत्रता का अधिकार / RIGHT TO FREEDOM (Art. 19-22)

CGL 6.06.2019

- 19(1)(d) देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता
- 19(1)(e) देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता
- ~~19(1)(f) संपत्ति का अधिकार\*~~
- 19(1)(g) कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता
- नोट: प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 (1)(a) में ही है।
- 19(1)(d) - to move freely throughout the territory of India;
- 19(1)(e) - to reside and settle in any part of the territory of India;
- ~~19(1)(f) - omitted by 44th amendment act. (it was right to acquire, hold and dispose of property)~~
- 19(1)(g) - to practice any profession, or to carry on any occupation, trade or business.
- Note: The freedom of the press is described in Article 19 (1) (a).

CGL - 6.03.2020

## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### स्वतंत्रता का अधिकार / RIGHT TO FREEDOM (Art. 19-22)

CGL – Pre 22,  
13.12.2022

**अनुच्छेद 20-** अपराधों के लिए दोष-सिद्धि के संबंध में संरक्षण- इसके तहत तीन प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है:

- (a) अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी न कि पहले और और बाद में बनने वाले कानून के तहत।
- (b) किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी।
- (c) किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

**Article 20 - Protection in respect of conviction for offences:**

- (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of the law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence
- (2) No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once
- (3) No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself

CHSL- 10.08.2021

## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### स्वतंत्रता का अधिकार / RIGHT TO FREEDOM (Art. 19-22)

CGL – 29.08.2016, Pre  
22, 1.12.2022

**अनुच्छेद 21-** प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण: किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

**अनुच्छेद 21(क)** - राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य, विधि द्वारा अवधारित करें, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ( 86वां संशोधन 2002 के द्वारा)।

**Article 21 - Protection of life and personal liberty:** No person can be deprived of his right to life and personal liberty except by the procedure established by law.

**Article 21 (a) - The state will provide free and compulsory education to all children between the ages of 6 to 14 in such a manner as the state may determine by law. (By 86th Amendment 2002).**

CGL – 29.08.2016, 16.08.2021, 10.11.2022, Pre 2022, 8.12.2022, 1.09.2016, 7.06.2019.  
CHSL- 10.10.2020, 12.08.21, 19.10.2020, 7.06.2019, 19.10.2020

CGL- 27.04.2014

**Article 21**, the success of democracy depends upon the right to personal liberty or personal liberty can be limited according to procedure established by law

- Right to privacy case study

अनुच्छेद 21, लोकतंत्र की सफलता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्भर करती है या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सीमित किया जा सकता है

- निजता का अधिकार मामले का अध्ययन

CHSL- 19.03.2018

A right to water, right to food and right to health health also mentioned in article 21

Rajasthan has the first state in India to make health a right of the people.

In 1985 Olga Yadav versus BMC decided to retain the right to livelihood under the right to life.

अनुच्छेद 21 में पानी का अधिकार, भोजन का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार का भी उल्लेख किया गया है

लोगों का स्वास्थ्य ठीक करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है।

1985 में ओल्गा येलो बनाम बीएमसी ने जीवन के अधिकार के तहत आजीविका के अधिकार को बरकरार रखने का फैसला किया।

**As per the interpretation by the Supreme Court of India, tapping of phone call, why did the fundamental rights provided in article 21 of the Constitution**

**भारत के सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार, फ़ोन कॉल की टाइपिंग, संविधान के अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार क्यों प्रदान किए गए?**



## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### स्वतंत्रता का अधिकार / RIGHT TO FREEDOM (Art. 19-22)

CGL – 10.09.2016



**अनुच्छेद 22-** कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण: अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो, तो उसे तीन प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है:

- (1) हिरासत में लेने का कारण बताना होगा।
- (2) 24 घंटे के अंदर (आने जाने के समय को छोड़कर) उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा।
- (3) उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा।

**Article 22- Protection against arrest and detention in certain cases:** If any person is arbitrarily detained, he is provided with three types of freedom:

- (1) The reason for detention has to be given.
- (2) He shall be produced before the Magistrate within 24 hours (except the time of arrival).
- (3) He shall have the right to consult the lawyer of his choice.

## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### स्वतंत्रता का अधिकार / RIGHT TO FREEDOM (Art. 19-22)

**निवारक निरोध:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड- 3, 4 ,5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत संबंधी कारणों से हो सकता है।

**Preventive Detention:** The provisions related to it are mentioned in sections 3, 4, 5 and 6 of Article 22 of the Indian Constitution. Under the Preventive Prevention Act, a person is arrested before committing a crime. The purpose of preventive detention is not to punish the person for the crime, but to prevent him from committing the crime. In fact, this preventive detention can be due to state security, public order maintenance or India related reasons.

## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### स्वतंत्रता का अधिकार / RIGHT TO FREEDOM (Art. 19-22)

CGL – 10.09.2016

जब किसी व्यक्ति निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब:

(a) सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक जेल में रख सकती है. अगर गिरफ्तार व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय के लिए जेल में रखना हो, तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है।

(b) इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, लेकिन जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है।

(c) निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए।

When a person is arrested under some method of preventive detention, then:

(a) The government can only keep such a person in jail for 3 months. If the arrested person is to be kept in jail for more than three months, then the report of the advisory board has to be obtained.

(b) The person so detained shall be informed as soon as possible on grounds of detention, but the facts which the revocation shall deem to be against the public interest are not required to be disclosed.

(c) The detained person should be given an early opportunity to make a representation against the restraining order.

## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### शोषण के विरुद्ध अधिकार / Right against Exploitation

अनुच्छेद	विवरण
23	मानव और दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध / Prohibition of traffic in human beings and forced labour
24	कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध / Prohibition of employment of children in factories, etc

## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### शोषण के विरुद्ध अधिकार / Right against Exploitation (Art. 23-24)

CHSL-  
26.10.2020

**अनुच्छेद 23:** मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध: इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद-बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है।

**नोट:** जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

**अनुच्छेद 24:** बालकों के नियोजन का प्रतिषेध: 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

**Article 23: Prohibition of human trafficking and forced labour:** It prohibits the purchase and sale of a person, forced labour and other similar forced labour, the violation of which is punishable according to law.

**Note:** Can be obliged to do national service when needed.

**Article 24: Prohibition of employment of children:** No child below the age of 14 years can be employed in factories, mines or any other risky job.

CGL – Pre 22, 3.12.2022  
CHSL- 6.08.2021



## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार / Right to Freedom of Religion

CHSL- 19.10.2020



अनुच्छेद	विवरण
25	अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता / Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion
26	धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता / Freedom to manage religious affairs
27	किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता / Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion
28	कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता / Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions



## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

CGL – 7.03.2020,  
Pre 22, 5.12.2022

### धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार / Right to Freedom of Religion (Art. 25-28) →

The main objective of this article is to sustain the principle of secularism also considered as the hallmark of democracy not allowed freedom for forcible conversion.

इस लेख का मुख्य उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को कायम रखना है, जिसे लोकतंत्र की पहचान भी माना जाता है, जिसमें जबरन धर्मांतरण की आजादी नहीं है।

CGL – Pre 22, 13.12.2022

## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार / Right to Freedom of Religion (Art. 25-28)

Rights implied duties means the right and duties go hand-in-hand.

Bold and impartial Judiciary is the most important safeguard of liberty and no one can restrained it.

अधिकार निहित कर्तव्यों का अर्थ है अधिकार और कर्तव्य साथ-साथ चलते हैं। निर्भीक और निष्पक्ष न्यायपालिका स्वतंत्रता की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है और कोई भी इस पर रोक नहीं लगा सकता है।

## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार / Right to Freedom of Religion (Art. 25-28)

Economic equality is not compatible with the liberal equality

Political liberty consist of light of individual to participate in government by voting and by holding public office.

आर्थिक समानता उदारवादी समानता के अनुकूल नहीं है

राजनीतिक स्वतंत्रता में व्यक्ति को मतदान करके और सार्वजनिक पद धारण करके सरकार में भाग लेने का अधिकार शामिल है।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार / Right to Freedom of Religion (Art. 25-28)

**अनुच्छेद 25:** अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता: कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार-प्रसार कर सकता है।

**अनुच्छेद 26:** धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता: व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संथाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि-सम्मत सम्पत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है।

**Article 25:** Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion: Any person may believe and propagate any religion.

**Article 26:** Freedom to manage religious affairs: A person has the right to establish and nurture institutions for his religion, acquisition, ownership and administration of lawful property.



## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार / Right to Freedom of Religion (Art. 25-28)

**अनुच्छेद 27:** राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है।

**अनुच्छेद 28:** राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते।

**Article 27:** The state cannot compel any person to pay such tax, whose income has been specially fixed for spending in the promotion or nurture of a particular religion or religious sect.

**Article 28:** Religious education will not be given in any education institution fully funded by state law. Such educational institutions cannot force their students to participate in any religious ritual or to listen to any sermon.

## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार / Cultural and Educational Rights

अनुच्छेद	विवरण
29	अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण / Protection of interests of minorities
30	शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार / Right of minorities to establish and administer educational institutions



## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार / Cultural and Educational Rights (Art. 29-30)

**अनुच्छेद 29:** अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा।

**अनुच्छेद 30:** शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार: कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी।

**Article 29:** Protection of Minority Interests  
A minority class can preserve its language, script and culture and will not be prevented from entering any government educational institution only on the basis of language, caste, religion and culture.

**Article 30:** Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions:  
Any minority class can run an educational institution of its choice and the Government will not discriminate in any way in granting it.



## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### सांविधानिक उपचारों का अधिकार / Right to Constitutional Remedies

अनुच्छेद	विवरण
32	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार / Remedies for enforcement of rights conferred by this Part
33	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति / Power of Parliament to modify the rights conferred by this Part in their application to Forces, etc.
34	जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन / Restriction on rights conferred by this Part while <b>martial law</b> is in force in any area
35	इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान / Legislation to give effect to the provisions of this Part

## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### सांविधानिक उपचारों का अधिकार / Right to Constitutional Remedies

'संवैधानिक उपचारों का अधिकार' को डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है।

Dr. Bhimrao Ambedkar has called the 'right to constitutional remedies' the soul of the Constitution.

**अनुच्छेद 32:** इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

**Article 32:** The right to apply in the Supreme Court has been given by appropriate proceedings to enforce fundamental rights under it.

## **भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS**

### **सांविधानिक उपचारों का अधिकार / Right to Constitutional Remedies**

अनुच्छेद 32 के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को पांच तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्न हैं:

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण
2. परमादेश
3. प्रतिषेध लेख
4. उत्प्रेषण
5. अधिकार पृच्छा लेख

With reference to Article 32, the Supreme Court has been empowered to remove five types of writ which are as follows:

1. Habeas Corpus
2. Mandamus
3. Prohibition
4. Certiorari
5. Writ of Quo Warranto

CGL -19.05.2013

**Article 33** item powers, the Parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of the member of the armed forces, paramilitary force, police force, intelligence agencies and Analogus forces.

**अनुच्छेद 33** मद शक्तियां, संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसियों और एनालॉग बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने की शक्ति देती है।



**Article 34** it provide for the restriction on fundamental rights while martial law is implemented in any area within the territory of India.

**अनुच्छेद 34** यह मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है जबकि भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया जाता है।



Article 35 Parliament shall has the power to make laws on fundamental rights but state legislature does not have this power.

Article 35 a gives the Jammu and Kashmir legislation Food. The Screenshots power to decide Oda for permanent resident of the state or in 1954. The article was revoked in on fifth of August 2019.

अनुच्छेद 35 संसद को मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति होगी लेकिन राज्य विधानमंडल के पास यह शक्ति नहीं है।

अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर विधान को भोजन देता है। स्क्रीनशॉट में ओडीए को राज्य के स्थायी निवासी या 1954 में तय करने की शक्ति है। अनुच्छेद को पांच अगस्त 2019 को रद्द कर दिया गया था।

**Four cases are important to understand the Basic structure**

**Shankari Prasad (1951)**

**Golak Nath (1967)**

**Keshavananda Bharati (1973)**

**Minerva mills (1980)**

## **भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS**

### **मौलिक अधिकार में संशोधन / Amendment in Fundamental Rights**

- सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद (1967) के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी यानी कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है।
- 24वें संविधान संशोधन (1971) द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया की अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।
- The Supreme Court in the decision of Golaknath v. Punjab Statehood (1967) stayed the amendment of Fundamental Rights through the procedure laid down in Article 368 i.e. that Parliament cannot amend the Fundamental Rights.
- Articles 13 and 368 were amended by the 24th Constitution Amendment (1971) and it was determined that the basic rights can be amended by the procedure given in Article 368.

## **भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS**

### **मौलिक अधिकार में संशोधन / Amendment in Fundamental Rights**

- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद (1972) के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया।
- 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।
- The decision in Kesavananda Bharti v. State of Kerala (1972) granted such an amendment to the statute, i.e., the decision of Golaknath v. State of Punjab was repealed.
- Clauses 4 and 5 were added to Article 368 by the 42nd Constitutional Amendment and it was arranged that such amendments cannot be questioned in any court.

## भाग III: मूल अधिकार / PART III: FUNDAMENTAL RIGHTS

### मौलिक अधिकार में संशोधन / Amendment in Fundamental Rights

- मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया।
- By the decision of *Minerva Mills v Union of India* (1980) it was determined that the court has the right to protect the basic features of the constitution and the court can review any amendment on this basis. The system made by the 42nd constitution amendment was also abolished.

**Shankari Prasad case**

- **SC opined that the power of the parliament to amend the constitution under Article 368 also includes the power to amend Fundamental Rights**
- **It based its judgment on the logic that the word 'law' mentioned in Article 13 includes only ordinary laws and not constitutional amendment acts**

**Golaknath case**

- **SC overruled its judgment**
- **It ruled in this that- Fundamental Rights are given a transcendental and immutable position and hence the Parliament cannot abridge or take away any of these rights**
- **It opined the constitutional amendment act is also a law under Art 13**
- **Parliament reacted to this judgment by enacting 24<sup>th</sup> amendment act which included a provision in Art 368 which declared that Parliament has power to take away any of the fundamental rights**

Keshavananda Bharati case

- SC overruled its judgment in the **Golaknath case**
- **It upheld the validity of the 24<sup>th</sup> amendment act and opined that parliament is empowered to take away or abridge any of the FRs. However, such changes should not alter the 'basic structure' of the constitution**

42<sup>nd</sup> CAA 1976

- **Amended Art. 368 – no limitation on the constituent power of Parliament.**
- **Any amendment cannot be questioned in any court on any ground.**



**Minerva mills case**

- **Parliament reacted to the above case by enacting 42<sup>nd</sup> amendment act which declared under article 368 that there is no limitation on the constituent power of Parliament and it barred the courts from questioning such amendments**
- **This provision was invalidated by the SC stating that Parliament cannot take away the 'judicial review' power of the constitution since it is part of the 'basic structure of the doctrine'**

**Waman Rao case 1981**

- **SC clarified that doctrine would be apply to constitutional amendments enacted after April 24, 1973 (Kesavananda Bharati case) (Including 9th schedule)**



---

**Some other  
facts related to  
Part 3**

---

**Right to vote is mentioned in the Constitution relating to fundamental rights**

**Indian Parliament has accepted the socialist pattern of society has objective of social economic policy**

**वोट देने का अधिकार संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित बताया गया है**

**भारतीय संसद ने समाज के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार करते हुए सामाजिक आर्थिक नीति का उद्देश्य अपनाया है**

Human rights under universal declaration, which includes the team and rights, act of education, right to public service at to life, liberty foods, freedom from slavery, torture, freedom of opinion, expression, right to work like education and many more.

On being criticised for boring feature from other countries for the Constitution Dr BR Ambedkar said nobody holds any patent right in the fundamental ideas of a Constitution

सार्वभौमिक घोषणा के तहत मानवाधिकार, जिसमें टीम और अधिकार, शिक्षा का कार्य, जीवन में सार्वजनिक सेवा का अधिकार, स्वतंत्रता भोजन, गुलामी से मुक्ति, यातना, राय की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, शिक्षा जैसे काम करने का अधिकार और बहुत कुछ शामिल हैं।

संविधान के लिए अन्य देशों की ओर से उबाऊ फीचर की आलोचना किए जाने पर डॉ. बीआर अंबेडकर ने कहा कि संविधान के मौलिक विचारों में किसी के पास कोई पेटेंट अधिकार नहीं है।

Part 3 is considered as the Magna Carta of India.

भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा माना जाता है

**Suspension of fundamental rights.**

**मौलिक अधिकारों का निलंबन.**

---



As per the Indian Constitution, Parliament can impose reasonable restriction over fundamental rights on the exercise of freedom of speech and expression on the ground of sovereignty and integrity of india




Security of state federation with foreign states, public order, decency or morality, contempt of court, defamation and incitement to an offence.





भारतीय संविधान के अनुसार, संसद सुनिधि और भारत की अखंडता के आधार पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है।


विदेशी राज्यों के साथ राज्य संघ की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि और किसी अपराध के लिए उकसाना।



These come under the condition of censorship  
fundamental right can be suspended in the case of  
national emergency.

As mentioned in the article 352 associated with national  
emergency imposed where ever there is a serious threat to  
security of India. Six fundamental rights under article 19  
hour automatically suspended in case of national emergency  
is imposed on the ground of war or still aggression which is  
article 358, give power to suspension of provision of article  
19 during emergencies.

Article 359 as the clause for suspension of  
other rights.



CGL- 21.04.2013, 21.04.2013.  
CHSL- 23.03.18, 5.07. 2019.

ये संसदशिप की शर्त के अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है।

जैसा कि अनुच्छेद 352 में बताया गया है कि जहां भी भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो वहां राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में अनुच्छेद 19 घंटे के तहत छह मौलिक अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं, युद्ध या अभी भी आक्रामकता के आधार पर लगाए जाते हैं जो कि अनुच्छेद 358 है, आपात स्थिति के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधान को निलंबित करने की शक्ति देता है।

अनुच्छेद 359 अन्य अधिकारों के निलंबन के खंड के रूप में।

CGL- 5.08.2017

**Article 20 & 21  
cannot be  
suspended.**

**अनुच्छेद 20 और 21  
को निलंबित नहीं  
किया जा सकता।**



The image features four hands of different skin tones arranged in a circle, with their palms facing inward. The hands are positioned at the top, bottom, left, and right, creating a protective or supportive frame around the central text. The text 'Fundamental Rights' is written in a large, blue, serif font, centered within the circle. A faint watermark with the number '24' is visible behind the text.

# Fundamental Rights

**Q1. Under which of the following articles, the Indian Constitution Guarantees Fundamental Rights to the citizens?**

**(UP Lower Sub. (Mains) 2015)**

- (A) Articles 12 to 35**
- (B) Only Articles 12 to 30**
- (C) Only Articles 15 to 35**
- (D) Only Articles 14 to 32**



**Q1. निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत लेख, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है नागरिक? (यूपी लोअर सब। (मेन्स) 2015)**

- (A) लेख 12 से 35**
- (B) केवल लेख 12 से 30**
- (C) केवल लेख 15 से 35**
- (D) केवल लेख 14 से 32**

## Q2. Freedom of News Papers in India

[Karnataka PSC (Pre) 2019]

- (A) Specially provided by Article 19(1)(a)
- (B) Is secured under Article 19(1)(b)
- (C) Secured by Article 361-A
- (D) Has origin by the enforcement of Rule of la

Q2. भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता  
[कर्नाटक पीएससी (प्री) 2019]

- (ए) विशेष रूप से लेख द्वारा प्रदान किया गया 19(1)(ए)
- (बी) अनुच्छेद 19 (1) के तहत सुरक्षित है (बी)
- (सी) अनुच्छेद 361-ए द्वारा सुरक्षित
- (डी) प्रवर्तन द्वारा मूल हैला के नियम का



**Q3. Which of the following are envisaged by the Right against Exploitation in the Constitution of India?/ निम्नलिखित में से कौन से हैं के खिलाफ अधिकार द्वारा परिकल्पित के संविधान में शोषण भारत?**

- 1. Prohibition of traffic in human beings and forced labour/ मानव के आवागमन पर रोक प्राणियों और मजबूर श्रम**
- 2. Abolition of untouchability/ अस्पृश्यता का उन्मूलन**
- 3. Protection of the interests of minorities/ के हितों का संरक्षण अल्पसंख्यकों**
- 4. Prohibition of employment of children in factories and mines/ के रोजगार पर रोक कारखानों और खानों में बच्चे**

**Select the correct answer using the code given below. [IAS (Pre) 2017]**

- (A) Only 1, 2 and 4**
- (B) Only 2, 3 and 4**
- (C) Only 1 and 4**
- (D) 1, 2, 3 and 4**



**Q4. In which Article of Indian Constitution Doctrine of Due Process of Law is included?  
[UPPCS (Mains) 2014]**

- (A) 11**
- (B) 16**
- (C) 21**
- (D) 26**

**Q4. भारतीय के किस अनुच्छेद में है देय का संविधान सिद्धांत कानून की प्रक्रिया शामिल है?  
[यूपीपीसीएस (मेन्स) 2014]**

- (A) 11**
- (B) 16**
- (C) 21**
- (D) 26**



**Q5. The authority to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights rests with whom ? (Ssc2016)**

- (a) All the courts in India**
- (b) The Parliament**
- (c) The Supreme Court**
- (d) The President of India**

**Q5. मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है?  
(एसएससी2016)**

- (ए) भारत में सभी अदालतों**
- (बी) संसद**
- (सी) सुप्रीम कोर्ट**
- (डी) भारत के राष्ट्रपति**



**Q6. On whom does the Constitution confer responsibility for enforcement of Fundamental Rights? (SSC 2016)**

- (a) All Courts**
- (b) President**
- (c) Parliament**
- (d) Supreme Court and High Courts**

**Q6. संविधान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी किसे देता है?**  
**(एसएससी 2016)**

- (ए) सभी न्यायालय**
- (बी) राष्ट्रपति**
- (सी) संसद**
- (d) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय**

**Q7. Choose the fundamental rights available to Indian Citizen but not to aliens.**

**[Delhi PSC (Pre) 2016]**

- 1. Freedom of Speech and Expression**
- 2. Equality Before the Law**
- 3. Right to Minorities**
- 4. Protection of Life and Liberty**

**(A) 1 and 3 (B) 1 and 4**

**(C) 2 and 4 (D) 2 and 3**

**Q7. मौलिक अधिकार चुनें भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है लेकिन नहीं एलियंस को।**

**[दिल्ली पीएससी (प्री) 2016]**

- 1. भाषण की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति**
- 2. कानून के समक्ष समानता**
- 3. अल्पसंख्यकों का अधिकार**
- 4. जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण**

**(A) 1 और 3 (B) 1 और 4**

**(C) 2 और 4 (D) 2 और 3**



**Q8. In the Indian Constitution, the right to equality is granted by five Articles. They are**

**[UP Lower Sub. (Pre) 2015**

**IAS (Pre) 2002]**

- (A) Article 16 to Article 20**
- (B) Article 15 to Article 19**
- (C) Article 14 to Article 18**
- (D) Article 13 to Article 17**

**Q8. भारतीय संविधान में, समानता का अधिकार पांच द्वारा प्रदान किया जाता है लेख। वे हैं**

**[यूपी लोअर सब। (प्री) 2015**

**आईएस (पूर्व) 2002]**

- (A) अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20**
- (B) अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19**
- (C) अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक**
- (D) अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17 तक**

**Q9. Consider the following statements/निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।**

**1. Article 301 is related to Right to Property./अनुच्छेद 301 अधिकार से संबंधित है संपत्ति।**

**2. Right to Property is a statutory right but not a Fundamental Right./संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक है सही है लेकिन मौलिक नहीं है सही।**

**3. Article 300-A was inserted in Indian Constitution by 44th Amendment during the period of Congress Government/अनुच्छेद 300-ए में डाला गया था 44वें द्वारा भारतीय संविधान अवधि के दौरान संशोधन कांग्रेस सरकार के।**

**Which of aforesaid statement is/are correct? [IAS (Pre) 2005]**

**(A) Only 2 (B) 2 and 3**

**(C) 1 and 3 (D) 1, 2 and 3**



**Q10. Which of the following rights are not available to all persons in India? / निम्नलिखित में से कौन से अधिकार हैं भारत में सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं?**

- 1. Equality Before the Law/ कानून के समक्ष समानता**
- 2. Right Against Discrimination/ भेदभाव के खिलाफ अधिकार**
- 3. Freedom to Move Freely throughout the Country/ आज़ादी से घूमने की आज़ादी-देश को मारो**
- 4. Right to Contest Election/ चुनाव लड़ने का अधिकार**

**Select your answer by using the code given below. / का प्रयोग कर अपने उत्तर का चयन करें नीचे दिया गया कोड।**

**[West Bengal PSC (Pre) 2019]**

**Code**

- (A) 1, 3 and 4**
- (B) 1, 2 and 4**
- (C) 1, 2 and 3**
- (D) 2, 3 and 4**

# Class24

## App download



**Class pdf**



**10 Questions test related to  
this class**

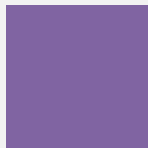
# Daily 3 most Important classes



**5 am - 10 min current affairs show**



**7 am - The Hindu Analysis**



**8 am - Daily SSC CGL/ CHSL Specific GK class**



# Test with Every Class

